लहूलुहान कश्मीर

'भारत का स्वर्ग' कही जाने वाली महर्षि कश्यप की धरती 'कश्मीर' एक बार पुनः लहूलुहान हुई है। यद्यपि यह सिलसिला आजादी के बाद हिन्दू राजा के पतन के साथ ही प्रारम्भ हो गया था। सन् आते यह चरम पर तब -आते 1990 पहुँचा जब एक ही दिन में कश्मीर केअन्दर हजारों कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई और लाखों को बेघर कर अपनी जन्मभूमि को ही छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। आज तक कश्मीरी विस्थापित हिन्दू वापस कश्मीर नहीं जा पाये। इस देश के अन्दर किसी भी सरकार ने अपने इस राष्ट्रीय कर्तव्य का निर्वाह ईमानदारी से नहीं किया कि अपनी ही मातृभूमि से विस्थापित नागरिकों को उनकी जन्मभूमि में वापस सुरक्षित भेजा जा सके। आज भी जम्मू, दिल्ली तथा देश के अन्य कई क्षेत्रों में लाखों कश्मीरी पंडित खानाबदोश की जिन्दगी जीने को मजबूर हैं। जब सन् में कश्मीर से बड़ी संख्या मे 1990ं हिन्दू विस्थापित हुआ तब देश के गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। जिनके कार्यकाल के दौरान पाकिस्तानी मुस्लिम आतंकवादियों को छोड़ने के लिये कथित रूप से उन्होंने अपनी पुत्री रूबिया सईद का अपहरण तक करवाया था और अन्ततः पाकिस्तानी आतंकवादी छोड़े गये। तब से कश्मीर की स्थिति दिनप्रतिदिन खराब होती गई। कश्मीर में ताजा - विरोध उसीमुफ्ती मोहम्मद सईद की शह पर उनकी पार्टी पीतथा भारत .पी.डी. विरोधी संगठनों द्वारा प्रारम्भ किया गया है। विरोध भी बड़ा हास्यास्पद है। कश्मी-तथा अन्य आतंकी संगठनों के विरोध का कारण जम्मू .पी.डी.पीर सरकार द्वारा "श्री अमरनाथ तीर्थ स्थल बोर्ड" जिसके अध्यक्ष जम्मूकश्मीर के राज्यपाल - हैं, को भूमि आवंटन किया जाना बताया जा रहा है। यह भूमि प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आवश्यक निर्माण कार्य हेतु आवंटित की गयी। इस प्रकार का आवंटन अक्सर धार्मिकसांस्कृतिक संस्थाओं को पूरे देश के अन्दर अपनी धर्मार्थ गतिविधियों के -

संचालन के लिए होते रहे हैं। यहवृहद् हिन्दू समाज की उदारता ही कही जायेगी कि पूरे देश के अन्दर सार्वजनिक भूमि कम अथवा अधिक संख्या में मदरसों, मकतबों अथवा कब्रिस्तान के नाम हुई है, हजारों स्थानों पर सार्वजनिक भूमि पर मजारें बनायी गयीं। लगभग प्रत्येक राज्य में हज हाऊस के नाम पर सार्वजनिक भूमि आवंटित हुई है। इसी प्रकार चर्च और उनके कब्रिस्तान के नाम पर भी सार्वजनिक जमीनें आवंटित हुई हैं। लेकिन कभी भी हिन्दू समुदाय ने अनावश्यक उसका विरोध नहीं किया। भूमि आवंटन के विरोध में कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा नहीं किया। क्या हिन्दुओं की इस उदारता को कमजोरी समझने की भूल कुछ समुदाय, संगठन अथवा इस देश का राजनीतिक नेतृत्व कर रहा है? जो अलगाववादी संगठन अथवा राजनीतिक दल अमरनाथ तीर्थस्थल बोर्ड को भूमि आवंटन का विरोध कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम कि इस देश में मन्दिरों के चढ़ावे का एक बड़ा हिस्सा हज सब्सिडी में खर्च हो रहा है? हिन्दू धर्म स्थलों के चढ़ावे के पैसे से हजयात्रा का उन्होंने कभी विरोध किया? और यही नहीं, प्रतिवर्ष मुहर्रम के जुलूस के नाम पर पूरे देश के अन्दर हजारों की संख्या में गरीब हिन्दुओं के मकान क्षतिग्रस्त होते हैं, तो पीपल और बरगद जैसे पवित्र वृक्षों को अनावश्यक काटकर हिन्दू भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ होता है। लेकिन इसका तो कोई संगठन अथवा सरकार विरोध नहीं करती अपितु उसे मुस्लिम समुदाय का मजहबी कर्म मान लिया जाता है। कश्मीर के वर्तमान घटनाक्रम के पीछे जो कुछ भी हो रहा है दरअसल वह इस्लाम के बुनियादी सिद्धान्तों के ही अनुरूप हो रहा है। यह भूल हमारी है कि हम आज भी इस्लाम के बर्बर, हिंसक एवं अत्याचारी चेहरे को पहचानने में भूल कर रहे हैं। यह विरोध वे ही लोग कर रहे हैं जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार रहे हैं। इन सबके बावजूद अगर हम मौन बनकर भारत माता के चीरहरण के वर्तमान दृश्य की अनदेखी करते जायेंगे तो न केवल - कश्मीर अपितु पूरे रा◌ाष्ट्र के अन्दर अलगाववादी गतिविधियों में लिप्त तत्वों का दुस्साहस ही बढ़ेगा। जो लोग इस राष्ट्र तथा इसकी सनातन परम्परा को समाप्त

करने का कुचक्र लगातार कर रहे हैं, उन तत्वों से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। अगर यह देश और इसका राष्ट्रीय समाज इसके प्रति सजग नहीं रहा तो उसे अपूरणीय क्षति से कोई बचा नहीं सकता।